बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 122 ● नई दिल्ली ● सोमवार 23 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

### बैंक लोन धोखाधड़ी- दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्म के खिलाफ आरोप तय रखने का फैसला रखा बरकरार

नई दिल्ली। छह करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में एक फर्म और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के खिलाफ तय किए गए आपराधिक आरोपों को रद करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने माना कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से गंभीर संदेह उत्पन्न होता है और इसके लिए पूर्ण सुनवाई आवश्यक है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश सकारात्मक रिपोर्ट में स्पष्ट अनियमितताओं और विरोधाभासों के बावजूद उनके अपराध में संलिप्तता को लेकर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है, जिसकी पुष्टि केवल ट्रायल में ही हो सकती है। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने विशेष सीबीआई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

# एसआईआर विवाद: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बंगाल में न्यायिक जांच आज से होगी शुरू, हर जिले में निगरानी करेगी समिति

**नई दिल्ली ।** बंगाल में चल रहे विशेष गहन निरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों की पूर्ण न्यायिक जांच सोमवार से शुरू हो जाएगी। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त 150 सेशन जज, 250 न्यायिक अधिकारी इस व्यवस्था में लगाए गए हैं। प्रत्येक जिले में हाई कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी। समिति में जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित जिला पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि फोकस 28 फरवरी तक 'लाजिकल डिस्क्रेपेंसी' श्रेणी में रखे गए मामलों की सत्यापन पूरा करने पर है, जो न्यायिक अधिकारियों को भेजे गए हैं। वर्तमान में तय किया गया है कि बंगाल में अंतिम मतदाता सूची समय पर 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, लेकिन उन मतदाताओं के दस्तावेजों को छोड़कर जिन्हें न्यायिक जांच के लिए भेजा गया है। बाद में पूरक सूचियां प्रकाशित की जाएंगी । अनुमान है कि न्यायिक जांच के दायरे में लगभग 45 लाख से 50 लाख मतदाताओं के दस्तावेज आएंगे, जो मुख्य रूप से लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी मामलों में हैं। इनमें प्रोजेनी मैपिंग के दौरान पाए गए असंगत पारिवारिक डेटा, असंगत जन्मतिथि, खाली या अस्पष्ट दस्तावेज आदि शामिल हैं। रविवार को उत्तर कोलकाता के जेसोप भवन में बैठक शुरू हुई, जिसमें जजों और चुनाव आयोग के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें सुनवाई की प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और समय सीमा के भीतर निपटारे का आउट लाइन अंतिम रूप दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों का ब्रिफिंग और ट्रेनिंग रविवार रात तक पूरा हो जाएगा, ताकि सोमवार से पूर्ण न्यायिक जांच शुरू हो सके।

### सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद बुलाई गई बैठक

सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सात सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक विशेष पैनल गठित करने का निर्णय लिया गया। यह पैनल अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले जटिल

मामलों और %लाजिकल डिस्क्रिपेंसी% विसंगतियों) का निपटारा करेगा। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में मौजूद तकनीकी और सूचनात्मक त्रुटियों को सुधारने के लिए हाई कोर्ट प्रशासन पूर्ण सहयोग देगा।

### सीजेआई ने किस बात पर जताई चिंता?

मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि इतने कम समय में 45 से 50 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन कैसे संभव होगा। चुनाव आयोग ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायिक अधिकारी की मांग की है, ताकि दस्तावेजों की जांच और निपटान की प्रक्रिया को गति दी जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार से ही इन दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य शुरू हो जाएगा। आयोग की ओर से जिला और विधानसभा वार विसंगतियों के आंकड़े उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके बाद स्क्रूटनी पूरी होने के बाद, आयोग द्वारा विस्तृत सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

### न्यायिक निगरानी में होगा सुधार कार्य

मुख्य न्यायाधीश के कक्ष में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मौजूद थे। तय रणनीति के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सात सेवानिवृत्त न्यायाधीश उत्तर और दक्षिण कोलकाता के विवादित मामलों की सुनवाई करेंगे। वहीं, जिलों में उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे की जिम्मेदारी वर्तमान या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को सौंपी गई है। यह पूरी प्रक्रिया सोमवार से युद्धस्तर पर शुरू हो जाएगी।

### सुपर-चेकिंग संदिग्ध मामले न्यायिक अधिकारी देखेंगे

निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, करीब 50 लाख मतदाता आवेदनों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। इनमें से 20 लाख मामले दस्तावेजों की कमी के कारण लंबित हैं, जबकि 30 लाख मामले ऐसे हैं जिन्हें स्थानीय चुनाव अधिकारियों (एईआरओ/ईआरओ) ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन आयोग की सुपर-चेकिंग में वे संदिग्ध पाए गए। अब ये तमाम विवादित मामले न्यायिक अधिकारियों के समक्ष रखे जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि रविवार तक इन न्यायाधीशों को पोर्टल और सिस्टम की तकनीकी जानकारी दे दी जाएगी ताकि सोमवार से सुनवाई सुचारू रूप से शुरू हो सके। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पोर्टल की पारदर्शिता पर चिंता जताई है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर कहा कि बंगाल के मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक योजना के अनुसार, 27 फरवरी तक जिन मामलों का निपटारा हो जाएगा, उन्हें मुख्य सूची में शामिल किया जाएगा। शेष मामलों को बाद में पूरक सूची के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार, दोनों ने ही इस न्यायिक हस्तक्षेप पर अपनी सहमति दे दी है, जिससे अब इस जटिल संवैधानिक प्रक्रिया के पारदर्शी तरीके से पूरे होने की उम्मीद जगी है।

# बदनाम ना करो!

देखो, देखो, इन मोदी विरोधियों की करतूत देखो। मोदी जी की छवि खराब करने के चक्कर में, देश को ही बदनाम कर दिया और वह भी अमृतकाल में। बताइए, बनियान पहन कर प्रदर्शन करने पहुंच गए। और प्रदर्शन भी कहां? जहां मोदी जी ने इतनी मेहनत से इतना बड़ा मेला लगाया था और सारी दुनिया के एआई उर्फ कृत्रिम मेधा वालों को जुटाया था कि आएं और विश्व गुरु की आई / आई का जलवा देखें। पर विरोधियों ने बना-बनाया खेल बिगाड़ दिया बल्कि देश को ही बदनाम कर दिया। देखना था, विश्व गुरु का एआई का जलवा, जहां बच्चा पहला शब्द ही आई बोलता है या एआई बोलता है और दुनिया ने देखे अधनंगे नौजवान; बदन के ऊपर के हिस्से पर सिर्फ बनियान या टी शर्ट पहने हुए और कई तो नंगे बदन हाथों में झंडे की तरह टी शर्ट उठाए हुए। और बनियान भी साफ-सफेद नहीं, उन पर भी नारे लिखे हुए। और तो और मोदी जी की तस्वीर तक टेढ़ी-आड़ी, उस पर से कंप्रोमाइज्ड का नारा भी। करा दी ना सारी दुनिया में थू-थू। दुनिया को दिखाना था आई का विश्व गुरु और दिख गया अधनंगा भारत! जिसे बाकी दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए मोदी जी की सरकार अठारह-अठारह घंटे मेहनत करती है। जिसे सारी दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए ऐसे मेलों-ठेलों से हफ्तों पहले से तमाम रेहड़ी-पटरी वालों को, ''अदृश्य'' कर देती है। दृश्य खराब करने वाली झुग्गी-झोपड़ियों से लेकर मोहल्लों तक को, कपड़े की दीवारों के पीछे गायब कर देती है। गोदी मीडिया को अतिरिक्त रोटियां डालकर चौबीसों घंटे सिर्फ मेला-मेला कराने के जरिए आंख ओट, पहाड़ ओट का इंतजाम करती है। उस सरकारी राज को देश के दुश्मनों ने सारी दुनिया को दिखा दिया और जहां सिर्फ मोदी जी की सोणी सी तस्वीर दीखनी थी, वहां उघड़े पेटों का मंजर दिखा दिया। अदालत ने एकदम सही किया, जो इन देश को बदनाम करने वालों को फौरन पांच-पांच दिन के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया। बल्कि हम तो कहेंगे कि पांच दिन तो बहुत कम हैं, इनके गुनाह को देखते हुए। इन्हें तो जिंदगी भर के लिए जेल में डाला जाना चाहिए। ऐसे देशद्रोहियों के साथ कोई नरमी बरतना ठीक है, क्या? यूएपीए का न सही, इन पर सरकारी राज विदेशियों पर जाहिर करने का मामला तो बनता ही है। एआई के मेले में, पेट का मुद्दा याद दिलाया है! इन्हें विश्व गुरु कभी माफ नहीं कर सकते। और यह सिर्फ दिल से माफ नहीं करने की बात नहीं है कि, दिल से माफी के बिना भी बंदा बाकी सब मौज-मजा करता रहे! इन्हें जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। ऐसी दुर्गति की जानी चाहिए कि मोदी जी के मेले-ठेले में, सरकारी राज पर से पर्दा हटाने की फिर किसी की हिम्मत न हो। वैसे शाह जी की पुलिस सही लाइन पर है। भारत को बदनाम करने की इस करतूत के पीछे जरूर गहरा षड्यंत्र है। जो इसे जनतंत्र, जनतंत्र में प्रदर्शन के बुनियादी अधिकार, वगैरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे या तो बहुत भोले हैं या राष्ट्र विरोधी हैं। जिस मेले में दुनिया भर के लोगों को न्यौता गया हो, वहां प्रदर्शन-वदर्शन का अधिकार कैसा? और पेट दिखाने का अधिकार तो हर्गिज नहीं। दुनिया के मेले में तो सिर्फ देश का नाम होता है या बदनामी होती है। सिंपल है, मोदी जी नाम कर रहे थे, प्रदर्शन करने वाले बदनाम कर रहे थे! रही बात दूसरे देशों में ऐसे मेलों में विरोध प्रदर्शनों की जगह रहने की, तो ऐसा करने वाले देश नौसिखिया हैं, अभी जनतंत्र की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। उनसे हमारे देश की क्या तुलना--हम डेमोक्रेसी की मम्मी वाले हैं!फिर षड्यंत्र रचने वालों के लिए कैसा जनतंत्र और कैसे जनतंत्र वाले अधिकार? और यह मामला तो विदेशी षड्यंत्र का है। मोदी-शाह के राज में बाकी सब चीजों में तो आत्मनिर्भरता है, पर षड्यंत्र सिर्फ विदेशी ही मंजूर है। खैर! यह तो सीधे चीन का हाथ है। यह नहीं भूलें यह पेट-दिखाऊ प्रदर्शन, विश्व गुरु को बदनाम करने की पहली या अकेली कोशिश नहीं थी। इसी आई मेले में इससे पहले भी कोशिशें हुई थीं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबो-कुकुर प्रकरण कौन भूल सकता है? उसके पीछे चीनी हाथ निकला था या नहीं? चीनियों ने पहले रोबो-कुकुर दिखाकर, भोले-भाले भारतीय विश्वविद्यालय को फंसाया। उन्हें यह कहकर भरमाया कि कुछ हजार डालर में कुकुर उनका। और तो और वे चाहें तो उसका अपने मन से नाम तक रख सकते हैं। गलगोटिया वालों भी बड़ा दिल दिखाया और कुकुर को नया नाम भी दिया-ओरियोन। अपने ओरियोन को उन्होंने पूरे दिल से मेले में सब को दिखाया भी और तो और, आईटी मंत्री जी की रील के जरिए, सारी दुनिया को उसका जलवा दिखाया भी। हम भारतीयों ने चीनी कुकुर को इतना अपनापन दिया, इतना प्यार दिया। और बदले में चीनियों ने क्या किया? विश्वासघात! ऐन मेले के बीच सारी दुनिया को बता दिया कि भारतीय विश्वविद्यालय ने तो सिर्फ रोबो-कुकुर को नया नाम दिया है, उसे बनाया तो चीनी कंपनी ने है। जाहिर है कि यह सब विश्व गुरु को बदनाम करने का षड्यंत्र था। और यह षड्यंत्र इतने पर ही खत्म नहीं हो गया। पर्ल्स चड्ढा नाम के जिस ट्विटर हैंडल ने रोबो कुकुर के चीनी मूल होने का शोर मचाकर, भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी, उसी ने बाद में गलगोटिया के ही स्टाल पर प्रदर्शित एक ड्रोन के कोरियाई मूल का भी मुद्दा उठा दिया। पर मोदी जी के होते हुए कोई साजिश सफल कैसे हो जाती? मोदी जी ने निर्णायक कार्रवाई की। भरे दिल से उन्हें गलगोटिया विश्वविद्यालय को मेले से रुखसत जरूर करना पड़ा, पर उन्होंने षड्यंत्र की जड़ पर फौरन आघात किया। मोदी जी ने पर्ल्स चड्ढा का ट्विटर हैंडल ही भारत में ब्लाक करा दिया। न रहेगा यह ट्विटर हैंडल और न उठेगा दिखायी गयी चीजों के, असली बनाने वाले का मुद्दा। और हां! क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी जी ने जब रोबो-कुकुर और ड्रोन की पैतृकता का शोर मचाकर, भारत के आई में भी विश्व गुरु होने के दावों को नुकसान पहुंचाने की इन कोशिशों को विफल कर दिया और आई में विश्व गुरु होने के भारत के दावे पर कोई आंच नहीं आयी, उनके बाद ही आया यह पेट दिखाऊ प्रदर्शन! और इसमें भी अमरीका के साथ ट्रेड डील के खिलाफ नारेबाजी। चीनी कनेक्शन के लिए, इससे बढ़कर दूसरा कोई सबूत क्या होगा?

# ट्रम्प की इकतरफा शुल्क नीति

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की वैश्विक शुल्क निर्धारण नीति को गैर संवैधानिक करार दिये जाने के बाद भारत से हुए इसके व्यापार समझौते की वैधता पर भी सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि श्री ट्रम्प ने जिस कानून 'इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' का इस्तेमाल करके दुनिया के विभिन्न देशों के बने माल पर अमेरिका में आयात होने पर शुल्क लगाने का काम किया है वह उन्हें इसका अधिकार ही नहीं देता है, अतः उनका आदेश असंवैधानिक है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दुनिया के विभिन्न देशों ने राहत की सांस ली है लेकिन श्री ट्रम्प ने अपने देश की सुरक्षा के तहत बने नियमों के तहत जिन आयातित उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया है उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय पीठ ने अपना फैसला 6-3 के बहुमत से देते हुए स्पष्ट किया कि शुल्क निर्धारण का अधिकार केवल अमेरिका की संसद (कांग्रेस) के पास है जिसे राष्ट्रपति लांघ नहीं सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राष्ट्रपति ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि भारत के साथ हुए व्यापार समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ज्ञातव्य है कि अमेरिका ने भारत के साथ अभी अन्तरिम समझौता ही किया है जिसका ब्यौरा अभी बन रहा है। अतः भारत के पास ऐसा हथियार आ गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इस ब्यौरे को तैयार करे और पुरानी शुल्क व्यवस्था की ओर लौटने का प्रयास करे। पुरानी व्यवस्था में अमेरिका को भेजे जाने वाले सामान पर अधिकतम तीन से चार प्रतिशत शुल्क की दरें प्रभावी थीं जबकि नये समझौते में इन्हें बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही समझौते में गैर शुल्कीय या नान टैरिफ शर्तें भी हैं जैसे भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल आयात करने पर भी अमेरिका ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी थी। इसे लेकर भारत की विरोधी पार्टियां व्यापार समझौते की कटु आलोचना कर रही थीं और इसे भारत की संप्रभुता से जोड़ रही थीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भारत सरकार के हाथ में ऐसा अस्त्र आ गया है कि वह समझौते की विभिन्न शर्तों को ढीला करा सके। अमेरिका के संविधान के अनुसार आपसी कारोबारी मुल्कों पर शुल्क निर्धारण करने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास होने की वजह से राष्ट्रपति ट्रम्प को अपनी वैश्विक शुल्क नीति को कांग्रेस के पास लेकर जाना चाहिए था मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अधिशासी आदेश जारी करके शुल्क नीति लागू कर दी। इससे अमेरिका की राजनीति में भूचाल आने की संभावना भी बढ़ गई है क्योंकि कांग्रेस में अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का भी अच्छा दबदबा है।

अमेरिका के इतिहास में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का इस्तेमाल शुल्क दर निर्धारण के लिए नहीं किया है।

मगर विगत वर्ष 2 अप्रैल को श्री ट्रम्प ने यह घोषणा की कि विदेशी कारोबार व आर्थिक प्रक्रियाओं के चलते अमेरिका में आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका के हितों को देखते हुए नई शुल्क नीति लागू करनी पड़ रही है। इसके बाद ट्रम्प ने विभिन्न कारोबारी देशों पर इकतरफा शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया था। इससे वर्ष 2025 के भीतर ही अमेरिका के राजकीय कोष में 142 अरब डालर की अतिरिक्त धनराशि जमा हुई थी।

मगर ट्रम्प के इस कदम से पूरी दुनिया के स्थापित विश्व क्रम में तूफान आ गया था और अमेरिकी शुल्कों ने एक हथियार का रूप ले लिया था। इस 142 अरब डालर की धनराशि में भारत से वसूली गई लगभग 49 करोड़ डालर की रकम भी शामिल है। अमेरिका ने सर्वाधिक धनराशि चीन से वसूली है। अतः सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन देशों को यह छूट मिल गई है कि वे नई शुल्क दरों के तहत अमेरिका को दी गई अतिरिक्त रकम की वापसी की मांग करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर चुप रहा है लेकिन जहां तक भारत का सवाल है तो फैसले से उसे फौरी लाभ तभी मिल सकता है जबकि समझौते की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग जाये और अमेरिका ने बढ़ी हुई शुल्क दर के हिसाब से भारत से अभी तक जो भी वसूला है उस रकम की वापसी हो। भारत अमेरिका को जो भी माल निर्यात करता है उसका लगभग 55 प्रतिशत ऐसा है जिसका अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के तत्वों से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर वहां के राष्ट्रपति को शुल्क बढ़ाने का अधिकार है, अतः ऐसे माल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुल्क दरें पूर्व की भांति हो हो जानी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सामान में धातु व इंजीनियरिंग मशीनरी आदि की वस्तुएं आती हैं। जाहिर है कि घरेलू सामान जैसे कालीन से लेकर हीरे-जवाहरात व आभूषणों तथा कपड़ों आदि का अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता जबकि भारत 55 प्रतिशत के लगभग ऐसा ही सामान अमेरिका को निर्यात करता है। मगर राष्ट्रपति ट्रम्प अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मिन्दा करने वाला बता रहे हैं, इससे उनकी मानसिक स्थिति का ही पता चलता है। पूरी दुनिया जानती है अमेरिका का लोकतन्त्र समूचे विश्व में सबसे खुला व पारदर्शी व जवाबदेह लोकतन्त्र है जिसमें वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति को उसकी संसद द्वारा बनाये गये संवैधानिक अनुदेशों पर ही चलना होता है। यहां का सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाये गये कानूनों की परख फिर संविधान की कसौटी पर करता है। अतः राष्ट्रपति ट्रम्प को अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए भारत के साथ हुए व्यापार समझौते की खुद ही तसदीक करनी चाहिए।

सम्पादकीय...

# 'हिय के शूल'

भारत सरकार की ओर से इस महत्वपूर्ण दिवस पर क्या कुछ विशेष कार्यक्रम होने हैं, कुछ पता नहीं चला। ऐसे में कहीं कोई कार्यक्रम आयोजित हुए होंगे भी तो वे निजी स्तर के ही कहे जायेंगे। वैसे प्रायः सभी राज्यों में वहां की भाषा अकादमियां हैं, जिनके लिए 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' पर कार्यक्रम आयोजित करना उनका प्राथमिक दायित्व है। लेकिन वहाँ भी मानो यही परिदृश्य है- 'रोअहू सब मिलिके आवहु भारत भाई, हा हा! भारत-दुर्दशा न देखि जाई। भक-दलील दी जा सकती है कि नयी शिक्षा नीति में तो मातृभाषा पर समुचित ध्यान और सम्मान दिया गया है। लेकिन जमीनी स्तर पर तो प्राथमिक शिक्षा में, जहां मातृभाषा में पठन-पाठन को अनिवार्य बनाए जाने को लेकर सुव्यवस्थित कार्ययोजना बनानी थी, उसकी जगह अब एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को जबरन लादा जा रहा है। मासूम-अबोध बच्चों की सोच-समझ को मातृभाषा में शिक्षा के माध्यम से विकसित करने के अहम् काम को दरकिनार कर, सबों के निश्छल दिल-दिमाग में ठू ठूंसने की कवायद युद्धस्तर पर की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिन आदर्श उद्देश्यों के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' मनाने की तिथि और उसके सकल उद्देश्यों की स्थापना की है, आज सबसे अहम् है। क्योंकि दुनिया के साथ साथ भारत देश भी विविध भाषाओं और संस्कृतियों वाला एक राष्ट्र है। ऐसे में 'बहु भाषा-संस्कृति की विशिष्टता और उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति' को स्थापित करना देशज के साथ साथ वैश्विक-बोध का कार्यभार बन जाता है। दुनिया के कई देश इस पर अमल करने की कोशिश करते रहे हैं, विश्वगुरु भारत के लिए मानो यह सब फानी जैसा है। उक्त सन्दर्भ विशेष में देखा जाय कि हिंदी समाज की मुख्यधारा में क्या स्थिति है, तो हालात बेहद निराशाजनक दीखते हैं। जिसके लिए आधुनिक हिंदी भाषा-साहित्य के जनक कहे जानेवाले भारतेंदु हरिश्चन्द्र कि उक्ति आज पूरी तरह से सत्य साबित हो रही है। उन्होंने आगाह करते हुए लिखा था- अंग्रेजी पढ़िके उन्नति सब गुन होत प्रवीन, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। ये बातें उन्होंने मातृभाषा के महत्व देने के सन्दर्भ कही थी कि- निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा-ज्ञान के मिटै न हिय को सूल। वैसे, इस सन्दर्भ में एक भारी विडम्बना यह भी है कि जिस हिंदी-पट्टी के क्षेत्र से कभी 'साझी-संस्कृति' की अविरल धारा ने 'गंगा-जमुनी तहजीब' बनकर पूरे सामाजिक परिवेश के भाषा-ज्ञान पर इतना गहरा असर डाला था कि 'हिंदी-उर्दू सगी बहनों' की मान्यता स्थापित हुई थी, आज वहीं सारा का सारा इलाका सत्ता-राजनीति संचालित उग्र धार्मिकता का भयानक् अखाड़ा बन चुका है। चुनावी ध्रुवीकरण और वोट के लिए बात-बात में हिन्दू-मुसलमान करना अचूक अस्त्र बना लिया गया है। सबसे बढ़कर, जहाँ से कभी 'निज भाषा-ज्ञान की गंगा' निकली थी, अब वहाँ उग्र सांप्रदायिक हिंसा-उन्माद और दकियानूस-कट्टर विचारों का जहरीला परनाला बहाया जा रहा है।

# भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस की बड़े आंदोलन की तैयारी!

अनिल जैन

पूर्व सेनाध्यक्ष एम.एम. नरवणे की किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर उठे विवाद के बाद अब खबर है कि केंद्र सरकार पूर्व सैन्यकर्मियों की किताब के प्रकाशन के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर रही है। इस बारे में रक्षा मंत्रालय में हाल में बैठक हुई, जिसमें ऐसे मामलों में सरकारी गोपनीयता कानून के प्रावधानों को भी लागू करने पर विचार हुआ। दरअसल, कार्यरत सैन्यकर्मियों के मामलों में तो विभिन्न वैधानिक एवं सेवा संबंधी शर्तें लागू होती हैं, लेकिन रिटायर्ड सैन्यकर्मियों की किताबों का प्रकाशन रोकने का कानून तो दूर, सेवा संबंधी नियम भी तय नहीं है।

सरकारी सूत्रों का दावा है कि रिटायर्ड सैन्यकर्मी भले सेना कानून या सेना के नियमों से बंधे हुए ना हों, मगर गोपनीयता संबंधी नियम उन पर भी लागू होते हैं। मगर मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं उसके संदर्भ में गोपनीय सूचनाओं की परिभाषा कौन तय करेगा? क्या नए नियम-कायदे राजनीतिक आम सहमति से तय होंगे या सत्ता पक्ष खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा का एकमात्र प्राधिकारी मानते हुए नियम तय कर देगा? यह समझ समस्याग्रस्त है कि सेना में अपनी पूरी कामकाजी जिंदगी गुजारने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा की परवाह नहीं करते अथवा सत्तासीन लोग विपक्षी दलों की तुलना में राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिक बड़े पहरुआ हैं। दरअसल, अधिकतम पारदर्शिता किसी सिस्टम के अंदर मौजूद कमियों दूर करने में अधिक सहायक होती है। किसी किताब से ऐसा प्रकरण या आम चलन सार्वजनिक होता है, जिससे नुकसान हुआ हो, तो उसे सामने आने देना चाहिए। उस पर पर्देदारी से तो राष्ट्रीय सुरक्षा कहीं अधिक क्षतिग्रस्त होगी।

**गांधी को भी एआई से बचाने की जरूरत**

देश के तमाम फिल्मी सितारे अपनी स्टाइल, अपनी आवाज और अपने संवाद के किसी भी रूप में इस्तेमाल पर अदालत से रोक लगवा रहे हैं। सबसे पहले जो अभिनेता इसके लिए अदालत पहुंचे थे उनमें एक अमिताभ बच्चन भी थे। बाद में तो सलमान खान से लेकर अजय देवगन और अभिषेक बच्चन से लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन तक सबने अदालत में गुहार लगाई और अपने पक्ष में आदेश प्राप्त किया। अदालतों ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति इन अभिनेता, अभिनेत्रियों के स्टाइल की नकल बिना अनुमति के नहीं करेगा। लेकिन फिल्मी सितारों से ज्यादा जरूरत महात्मा गांधी को ऐसी चीजों से बचाने की है। पिछले महीने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी के आसपास कांग्रेस और भाजपा दोनों की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए महात्मा गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल करके एक दूसरे के खिलाफ संदेश प्रसारित कराया गया। किसी वीडियो में ऐसा लगा, जैसे महात्मा गांधी भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं तो किसी में लगा कि वे भाजपा की आलोचना कर रहे हैं। इस किस्म के एआई जेनरेटेड वीडियो के खिलाफ कई सामाजिक संगठनों और गांधीवादी संस्थाओं ने साइबर अपराध शाखा को शिकायत दर्ज कराई। असम कांग्रेस ने भी इसकी शिकायत की। लेकिन यह सिर्फ पुलिस का मामला नहीं है। सभी पार्टियों और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

**व्यापार संधि के खिलाफ उतरेगी कांग्रेस**

लगता है कि कांग्रेस जो काम मनरेगा बचाओ आंदोलन में नहीं कर पाई, वह अमेरिका के साथ व्यापार संधि के मामले में करना चाहती है। राहुल गांधी ने इसका माहौल बना दिया है। उन्होंने चार दिन तक लगातार सोशल मीडिया में व्यापार संधि की शर्तों को लेकर सरकार पर हमला किया। राहुल ने सबसे ज्यादा किसानों के मुद्दे पर फोकस किया। किसानों ने केंद्र सरकार के तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस कराया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने किसानों से जो वादा किया वह चार साल बाद आज तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात यह कि किसानों के संगठन भी मान रहे हैं कि अमेरिका के साथ हुई व्यापार संधि से किसानों को नुकसान होगा। इसीलिए कांग्रेस इस संधि के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। मार्च में इस प्रदर्शन का ऐलान हो सकता है। मार्च में ही इस व्यापार सौदे पर दोनों देश दस्तखत करने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस इस मसले पर आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं से राहुल गांधी और खड़गे की मुलाकात होगी। राहुल ने सबसे पहले कपास किसानों का मुद्दा उठाया था। इस लिहाज से महाराष्ट्र के नेताओं से उनके मिलने का संदर्भ समझ में आ रहा है। बाकी राज्य भी खेती किसानी वाले राज्य हैं। अमेरिका और न्यूजीलैंड के सेब के लिए भारत का बाजार खोलने से सेब उत्पादक भी परेशान हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आंदोलन की तैयारी हो रही है।

**हरदीप पुरी का जाना तय है!**

एपस्टीन फाइल से विवादों में आए हरदीप पुरी का मामला हालांकि धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है। उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाली तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के हमले की तीव्रता भी कम हो गई है, कांग्रेस का हमला जारी है। पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। उनका कहना है कि एपस्टीन से पुरी 14 बार मिले हैं। बहरहाल, विपक्षी पार्टियों की ओर से हरदीप पुरी के खिलाफ जो भी अभियान चल रहा हो लेकिन सत्तापक्ष की ओर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन पुरी को है। वे कम से कम फिलहाल इस मसले पर पुरी का इस्तीफा नहीं लेने जा रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते 15 फरवरी को हरदीप पुरी को जन्मदिन की बधाई देकर भी संकेत दे दिया था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। हालांकि जानकार सूत्रों का कहना है कि मई या जून में जब प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में फेरबदल करेंगे तब पुरी की विदाई हो जाएगी। गौरतलब है कि हरदीप पुरी का राज्यसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में खत्म हो रहा है। अभी वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें फिर से उच्च सदन में नहीं भेजा जाएगा। मी टू में फंसने के बाद एमजे अकबर भी ऐसे ही इस्तीफा देकर हटे थे और जल्दी ही राज्यसभा में उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उसके साथ ही उनके राजनीतिक करियर पर भी विराम लग गया।

**देखा-देखी रंग बदलते राज्यपाल**

जैसे खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है वैसे ही इन दिनों राज्यपाल भी एक दूसरे को देख कर रंग बदल रहे हैं। राज्यपालों का इस साल का रंग विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों में अभिभाषण नहीं पढ़ने का है। एकाध अपवाद को छोड़ कर विपक्षी शासन वाले सभी राज्यों में राज्यपालों ने अभिभाषण नहीं पढ़ा या दो चार लाइन पढ़ कर छोड़ दिया। पहले कभी ऐसा अपवाद के तौर पर हुआ था। अब यह मुख्यधारा की बात हो गई है। यह तो सब जानते हैं कि राज्यपाल राजनीतिक व्यक्ति होते हैं और केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। फिर भी आमतौर पर राज्यपाल न्यूनतम मर्यादा और नैतिकता का निर्वाह करते हुए कम से कम तटस्थता दिखाने की कोशिश जरूर करते थे। लेकिन अब राज्यपाल ने वह शर्म, लिहाज, नैतिकता आदि का चोला पूरी तरह से उतार दिया है। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने इस साल के पहले विधानसभा सत्र में अभिभाषण नहीं पढ़ा। उनकी देखा-देखी केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भी नहीं पढ़ा। फिर उनकी देखा-देखी कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी पूरा अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया।

अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी दो-चार लाइन पढ़ कर अभिभाषण छोड़ दिया। राज्य सरकार की ओर से लिखा गया अभिभाषण पढ़ना राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है। लेकिन राज्यपालों

# असम में कांग्रेस-भाजपा क्या है गम?

असम में चुनाव सिर पर है, सो सियासी बाजीगरियों का दौर रोज-ब-रोज नई अंगड़ाइयां मार रहा है, अभी पिछले दिनों असम कांग्रेस के पूर्व सिरमौर भूपेन बोरा ने भगवा दामन थाम लिया। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बोरा को भाजपा के करीब लाने में असम के एक सीनियर पत्रकार की महती भूमिका रही। यह भी कहा जाता है कि भाजपा संग बोरा की 'डील लॉक' कराने में इस पत्रकार महोदय ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, उन्होंने अपने फोन से पहली दफे बोरा की असम के चीफ से बात कराई। कहते हैं किसी भांति बोरा व उस भाजपा सिरमौर की पूरी बातचीत पत्रकार महोदय के फोन में रिकार्ड हो गई। जिसमें भाजपा के यह बड़बोले क्षत्रप बोरा से यह पूछते हुए सुनाई देते हैं कि 'आप अपनी पार्टी से और कितने प्रमुख लोगों को भाजपा ज्वॉइन करा सकते हैं?' उसमें जवाब में असम के एक निवर्तमान कांग्रेसी सांसद का नाम लिया जाता है, साथ ही यह भी बताया जाता है कि प्रदेश के कम से कम 4 कांग्रेसी विधायक भाजपा में आने को तैयार हैं, फिर इन विधायकों के नाम बताए जाते हैं, दूसरी ओर से कहा जाता है- 'अरे इनमें तो दो मुसलमान एमएलए हैं, ये हमारे किस काम के, आप उस सांसद वाली डील फाइनल कराइए।' अपना काम खत्म करने के बाद इस पत्रकार महोदय ने भाजपा के उसी बड़बोले क्षत्रप को फोन लगाया और कहा-'मशन जॉब इज़ डन।' दूसरी ओर एक दंभ भरी आवाज में जवाब आया-' चिंता मत करो, तुम्हारा रेट तुम्हें मिल जाएगा।' हक्का-बक्का रह गए उस सीनियर पत्रकार ने इसे अपनी तौहीन समझी और माना जाता है कि उन्होंने तैश में आकर अपने फोन की सारी रिकार्डिंग असम कांग्रेस के बड़े नेता गौरव गोगोई को सौंप दी और कहा- 'कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूरी रिकार्डिंग आप वहां मौजूद मीडिया को सुना देना, असम में सियासी बवाल मच जाएगा।' कहते हैं बड़े नेताओं को गोगोई ने वह रिकार्डिंग उन्हें सौंप दी, जब यह पूरी बातचीत सुनी तो दंग रह गए कि यहां कांग्रेस के नेता भी अपने रेट लगवा रहे हैं। सो, उन्होंने गौरव को सलाह दी कि 'फिलहाल इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देने में ही भलाई है अन्यथा इस रिकार्डिंग के बाहर आने से कांग्रेस की भी उतनी ही फजीहत होगी।' जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हामिद कारा के खिलाफ अब राज्य में बगावत ने आकार लेना शुरू कर दिया है, पिछले कोई डेढ़ वर्षों से कारा पर यही आरोप बार-बार लग रहे हैं कि वे राज्य में पार्टी को एकजुट रखने में अब तक नाकाम साबित हुए हैं। पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर के कांग्रेसी नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, पहले तो ये राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, पर राहुल इन दिनों काफी व्यस्त हैं, सो जब इन नेताओं का राहुल से मिलना संभव नहीं हो पाया तो ये कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के पास धमक पड़े, अपने 'कारा हटाओ, पार्टी बचाओ' का उद्घोष लेकर। अब खड़गे साहब की दुविधा यह है कि वे इस मामले में ज्यादा अपनी नाक नहीं घुसाना चाहते क्योंकि वे जानते हैं कि हामिद कारा राहुल गांधी की पसंद रहे हैं और राहुल ने ही उनका चयन जम्मू-कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष के लिए किया था, अब पार्टी की जम्मू इकाई ने भी 'कारा हटाओ' अभियान में कंधा से कंधा मिला लिया है, इनकी मांग तो थोड़ी और अलहदा है, ये चाहते हैं कि जम्मू के किसी हिंदू लीडर को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए जिससे यहां भाजपा के मजबूत हिंदू आधार में सेंध लगाई जा सके। स्मरण रहे कि कभी जम्मू संभाग कांग्रेस का एक मजबूत आधार हुआ करता था, आखिरी बार कांग्रेस ने कोई हिंदू प्रदेश अध्यक्ष बनाया था वह भी महज कुछ समय के लिए, पर यह बात भी चार दशक पुरानी हो गई है। वहीं कारा से असंतुष्ट नेताओं का एक बड़ा वर्ग जम्मू-कश्मीर के एआईसीसी प्रभारी सैयद नासिर हुसैन से भी उतने ही नाराज हैं क्योंकि वे पिछले काफी समय से कारा विरोध की अनदेखी करते आ रहे हैं, वे बार-बार असंतुष्ट नेताओं के समक्ष बस यही जुमला दुहराते रहते हैं कि 'इन्हें थोड़ा वक्त और दे दो।' कारा पर आरोप है कि वे अध्यक्ष रहते कश्मीर में एक भी उल्लेखनीय पार्टी कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए हैं। यह तो कारा के विरोधी भी जानते हैं कि बगैर राहुल गांधी की सहमति के कारा को यहां से रूखसत कर पाना नामुमकिन है। पर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, क्योंकि नासिर हुसैन जैसे नेताओं को राहुल के आगे मुंह खोलने की हिम्मत नहीं, असंतुष्ट नेताओं को राहुल मिलने का वक्त ही नहीं देते। सो, अब ले देकर सबकी निगाहें एआईसीसी महासचिव और कश्मीरी नेता जी.ए. मीर पर टिक आई हैं, जिनकी इन दिनों हाईकमान से ज्यादा बनती नहीं, पर वे चाहे तो डंके की चोट पर राहुल के आगे अपनी बात रख सकते हैं।

पंजाब के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल और भाजपा में चुनावी तालमेल पर सहमति बन चुकी है। अब तक यह बात भाजपा और अकाली दल दोनों समझ चुके हैं कि जब तक हिंदू वोटरों का रूझान आम आदमी पार्टी से कम नहीं होगा प्रदेश में आप की संभावनाओं को धूमिल कर पाना मुश्किल कार्य है, अगर हिंदू वोट एकजुट होकर भाजपा गठबंधन की झोली में आते हैं तो आगे की लड़ाई वहां त्रिकोणात्मक हो जाएगी। खास कर सिख व पंजाबी वोटर अकाली दल, कांग्रेस व आप में बंट सकते हैं। दलित वोटरों का स्वाभाविक रुझान इस दफे कांग्रेस की ओर पहले से दिख रहा है। अकाली-भाजपा गठबंधन की नई आधारशिला रखने का सबसे पहला क्रेडिट सुखबीर सिंह बादल को जाता है। सबसे पहले बादल भाजपा के बड़े नेता से मिलने दिल्ली पहुंचे और भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में अपनी सहमति दिखाई। बड़े नेताजी को इस बात के लिए तैयार करने में भी कामयाब रहे कि 'अकाली दल इस गठबंधन का सीनियर पार्टनर रहेगा और वे यानी सुखबीर गठबंधन के सीएम फेस रहेंगे और इस चुनाव में भाजपा अपना पूरा धन, बल व तंत्र झोंक देगी।' कहते हैं इस मुलाकात के बाद समझौते के प्रारंभिक स्वरूप पर सहमति बन गई। सुखबीर जब लौट कर घर आए तो माना जाता है कि उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल उनसे बेतरह नाराज थीं, क्योंकि सुखबीर ने अपने साले विक्रम मजीठिया की जमानत व रिहाई को लेकर बड़े नेता जी से कोई बात नहीं की थी। कहते हैं इसके बाद हरसिमरत कौर की तरफ से बड़े नेता से मिलने का समय मांगा गया, समय मुकर्रर हुआ और इस मुलाकात में हरसिमरत ने भाजपा नेता से अपने लिए बस एक ही फेवर मांगा कि 'गुड विल जेस्चर' के तहत उनके भाई विक्रम मजीठिया को बेल मिल जाए ताकि भाजपा-अकाली दल में फिर से एक नए रिश्ते की शुरूआत हो सके।' क्या यह महज इत्तफाक था कि इसके कुछ दिनों बाद ही मजीठिया बेल पर छूट कर जेल से बाहर आ गए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रतिकूल आया हो पर ट्रंप अपने पुराने तेवरों से टस से मस नहीं हो रहे। सूत्र बताते हैं कि 'अगर बातचीत अब भी फेल रही तो ट्रंप एक मार्च या उसी सप्ताह में ईरान पर स्ट्राइक का ऑर्डर दे सकते हैं।' इस बात की संभावना और भी बलवती होती जा रही है क्योंकि अमेरिका ने ईरान को पांच प्रमुख प्वाइंट्स से घेर लिया है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजों की तैनाती अपने पूरे उफान पर है।

ट्रंप ने अभी संकेत दिया है कि 'ईरान पर फिलहाल सीमित हमला होगा। जिसके केंद्र में उसके मिलिट्री बेस होंगे, अमेरिका ने अभी ईरान को समझौते पर दस्तखत करने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी है। ईरान ने इस पर सोचने के लिए अभी चार दिनों का वक्त मांगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अपनी नेवी और एयर स्ट्राईक से 'टारगेट' हमला कर सकता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान की मौजूदा लीडरशिप बेहद कमजोर हो, उसकी विदाई हो और उसकी जगह वहां लोकतंत्र की बहाली हो।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पंचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/0882)

# कमलेश कुमार जी की जयंती पर किया चाय-ताहरी वितरण

## दी भावभीनी श्रद्धांजलि

मुरादाबाद।

स्वर्गीय कमलेश कुमार की जयंती के अवसर पर उनके द्वारा स्थापित किए गए श्री रामलीला महासंघ द्वारा उनके आदर्शों को जीवंत रखते हुए सेवा का एक मार्मिक आयोजन किया गया। स्वर्गीय कमलेश कुमार द्वारा स्थापित संस्था श्री रामलीला महासंघ के कोषाध्यक्ष छोटे भाई, शैलेंद्र अग्रवाल और कमलेश कुमार जी के पुत्र कुमार देव (संस्था के महामंत्री) द्वारा बैनर तले आमजन के लिए निःशुल्क चाय और ताहिरी का वितरण किया गया। इस अवसर पर वातावरण केवल श्रद्धांजलि का नहीं, बल्कि संवेदनाओं और संस्कारों का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत दो मिनट के मौन रखकर की गई, जिसमें उपस्थित लोगों ने कमलेश कुमार जी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके पश्चात उनके जीवन, संघर्ष और सामाजिक सरोकारों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया। शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि स्वर्गीय कमलेश जी ने जीवनभर समाज सेवा को ही अपना धर्म माना और आज श्री रामलीला महासंघ उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है।सेवा कार्य के अंतर्गत जरूरतमंदों, राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को स्नेहपूर्वक चाय और ताहिरी परोसी गई। ब'चों को फैन



वितरण भी किया गया। आयोजन में सादगी थी, लेकिन भावना अत्यंत भव्य थी। कई लोगों ने कहा कि आज के समय में जब लोग स्मृति दिवस केवल औपचारिकता के रूप में मनाते हैं, तब सेवा के माध्यम से श्रद्धांजलि देना वास्तव में प्रेरणादायक है। कार्यक्रम स्थल पर स्वर्गीय कमलेश कुमार जी का चित्र एवं उनके प्रेरक विचारों से सुस'जित फ्लेक्स भी लगाया गया था, जिसके समक्ष लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा व्यक्त की। उपस्थित जनों ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में सेवा संस्कार को जीवित रखने का संदेश है। इस अवसर पर संस्था के लोगों ने मिलकर कहा कि कमलेश जी का साया भले ही सिर से उठ गया हो, लेकिन उनके संस्कार और सेवा का मार्गदर्शन आज भी हमारे साथ है। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि स'ची श्रद्धांजलि शब्दों से नहीं, कर्मों से दी जाती है। पूरा कार्यक्रम आत्मीयता और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। लोगों ने इसे एक आदर्श और अनुकरणीय पहल बताते हुए आयोजक संस्था/परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। सेवा, संवेदना और संस्कार के संगम से सजी यह जयंती वास्तव में समाज के लिए प्रेरणा का संदेश बन गई। समस्त आयोजन का संचालन एडवोकेट श्री राम शर्मा द्वारा किया गया। इस आयोजन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता, वरिष्ठ रंग कर्मी डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार बिजनौर टाइम्स सुशील कुमार शर्मा, शिवसेना (उबठ) के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा, मेहुल रस्तोगी, बबलू रस्तोगी, आलोक राठौर, नरेंद्र कुमार, कैलाश गुप्ता, हरिओम अग्रवाल, सत्येंद्र, सिद्धार्थ, आदित्य, अभिजीत, अरुण वर्मा, शरद सक्सेना आदि ने अपनी भावनात्मक उपस्थित दर्ज कराई।

# सीता रसोई ने किया निःशुल्क भोजन का वितरण

मुरादाबाद।

सीता रसोई के द्वारा चलते-फिरते राहगीरों को निशुल्क भोजन वितरित किया गया। सीता रसोई के अध्यक्ष उदयभान सिंह ने बताया कि आज जो भोजन का वितरण किया गया है वह प्रायोजित रहता है। आज के भोजन में सहयोग श्रीमती यशिका गर्ग, गीतिका गर्ग एवं गरिमा अग्रवाल के द्वारा पूरी सब्जी और हलवे कई व्यवस्था की गई जिसको सभी लोगों ने भरपूर आनंद के साथ प्रसाद ग्रहण किया सीता रसोई पर आज साधु संतों की मंडली भी आई जिसमें से भजनों की प्रस्तुति से पूरे पंडाल को संगीत में कर दिया। सर्वप्रथम भगवान राम की स्तुति करते समय संस्था के संरक्षक पुनीत अग्रवाल ने दीप प्र'वलित करके श्री राम की स्तुति की गई। उसी क्रम में संरक्षक हृदय कुमार सिंह ने आए हुए अतिथियों का स्वागत बंधन किया संस्था के संरक्षक एव कोषाध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा जी ने बताया कि संस्था किसी प्रकार से कोई सरकारी सहयोग नहीं लेती है। महिला विंग की अध्यक्ष सुप्रीत सिंह ने बताया कि संस्था के द्वारा आने वाले होली के त्योहार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा इसके लिए जल्दी ही संस्था की बैठक आयोजित की जाएगी आज के भोजन वितरण में व्यवस्था में प्रमुख रूप से सहयोग करता के रूप में विवेक कुमार पांडे दीपक गुप्ता संजीव शर्मा राकेश कुमार वर्मा सत्य प्रकाश वार्ष्णेय जूही माथुर राजेश सक्सेना सुनील कपूर पवन कपूर श्रीपाल राणा धर्म प्रकाश शर्मा नीरज गुप्ता मनोज गिरी संजीव शर्मा धीरज गुप्ता सहित सीता रसोई परिवार के लोगों ने उपस्थित रहकर के भोजन वितरण में सहयोग प्रदान किया।

# रमज़ानः खजला, फैनी और डबल रोटी की खूब हो रही खरीदारी



मुरादाबाद।

रमजान के मुबारक महीने में शहर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की रौनक देखते ही बनती है। बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ गई है। सुबह से लेकर शाम तक इबादत के बाद रात को जमकर खरीदारी हो रही है। मुरादाबाद में फैनी-खजला और खजूर की डिमांड सबसे ज्यादा है। रमजान को लेकर बाजार में रौनक का माहौल बना हुआ है। लोग फलों के अलावा खजला, फैनी, डबल रोटी, सिवइयां और खजूर आदि की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों में भी उत्साह का माहौल हुआ है। आलम यह है कि देर रात तक बाजार गुलजार है। इन दिनों रमजान में इफ्तार और सहरी के समय खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की खरीदारी खूब हो रही है। ज्यादातर भीड़ शाम से लेकर देर रात तक नजर आ रही है। फैनी और खजला 240 रुपये किलो है तो रंग बिरंगी कचरी 60 रुपये किलो और सफेद कचरी 80 रुपये किलो है। इसमें साबूदाना की कचरी का दाम 200 रुपये किलो है। डबल रोटी 40 रुपये से लेकर 300 रुपये की है। देसी घी की डबल रोटी 100 रुपये की है। सिवइया 50 रुपये 100 रुपये किलो तक है। देसी घी की फैनी और खजला का भाव 600 रुपये है। इसके अलावा ईरानी खूजर की खरीदारी खूब हो रही है। ईरानी खजूर 120 रुपये किलो है तो कीमिया खजूर 300 रुपये किलो बिक रही है। वहीं फलों की खरीदारी भी लोग जमकर कर रहे हैं। लोगों द्वारा खरीदारी किए जाने से दुकानदारों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि रमजान के महीने में काम ठीक चल रहा है। देर रात तक लोग खरीदारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि रमजान महीने में काम काफी बेहतर रहेगा।

# अपमान का नहीं कोई मामला, यूं ही दिया गया तूल-मंज़र यार

**पार्टी मुखिया की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी- जिला महासचिव**

फतेहपुर।

फतेहपुर आए समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पीछे खड़े सपा जिला महासचिव चौधरी मंज़र यार को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ और जिला महासचिव के अपमान की बात की गई। उसी वीडियो में वरिष्ठ सपा कार्यकर्ता एवं थरियांव प्रधान मोतीलाल यादव को भी देखा जा सकता है, जिन्हें सपा सांसद नरेश उत्तम व सुरक्षा अधिकारी पीछे खींच रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि शायद व्यवस्था एवं अनुशासन पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। प्रेस वार्ता के दौरान यदि सभी को फोटो खिंचानी थी तो क्या उसी प्रकार बैठने की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए थी ? इसके साथ ही क्या मीडिया बंधुओं के लिए भी बैठने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी ? इन सवालों पर सपा जिला महासचिव चौधरी मंजर यार ने कहा कि अपमान जैसी कोई बात नहीं है, मामले को यूं ही तूल दिया गया। अखिलेश यादव पार्टी के मुखिया हैं और हम सब पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। उनकी सुरक्षा, हम सब की जिम्मेदारी है।

# राजेंद्र सिंह एकैडमी में प्रथम वार्षिकोत्सव की रही धूम

मेजा प्रयागराज।

प्रयागराज के मेजा स्थित राजेन्द्र सिंह एकेडमी में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कृष्णा नगर, हनुमानपुर, सिरसा में स्थित एकेडमी के प्रांगण मे किया गया। इसका उद्देश्य विद्यालय के छात्रों की प्रतिभा, परिश्रम और कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करना है। कार्यक्रम के आयोजक श्याम कृष्ण पप्पू पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत सिरसा व मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज सांसद उज्जवल रमण सिंह रहे। इस विशेष अवसर पर छत्र-छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गयी। इन प्रस्तुतियों में भारतीय संस्कृति, देशभक्ति और सामाजिक संदेशों का समावेश रहा।

यह आयोजन बच्चों की कलात्मक क्षमताओं को निखारने और उन्हें मंच प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहें। विद्यालय प्रबंधक ने क्षेत्रवासियो व अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के समस्त स्टाफ और राजेन्द्र सिंह एकेडमी के प्रबंधक तथा नगर पंचायत सिरसा के पूर्व चेयरमैन श्याम कृष्ण सिंह उर्फ पप्पू यादव द्वारा किया गया है। श्याम कृष्ण सिंह ने कहा, बच्चों की मुस्कान और उनकी कला ही भविष्य की नींव है। आइए, इस नींव को अपने स्नेह से सींचें।-नेताओं में शैलेंद्र यादव सुरेश ठेकेदार काशी नरेश यादव नीरज यादव शिव कैलाश यादव विमल यादव उर्फ लोहिया विमल पासी अवधेश यादव कमलचंद यादव अंबाजू भाई, राहुल यादव आदिराम राज पटेल प्रधानाचार्य मंच संचालन प्रीति यादव नें किया लोगों नें काफ़ी सराहना की, विनय यादव सरिता यादव प्रियांशी यादव ममता यादव नेहा यादव नैंसी गौतम अखिलेश यादव अखिलेश सोनकर आकृति केसरी वंदना यादव सीमा यादव रवि केसरी अंश कृष्ण और वंश कृष्णा आदि लोग उपस्थित रहे।





**बच्चों की मुस्कान व उनकी कल ही भविष्य की नीव है -श्याम कृष्ण यादव**

# विधिक जागरूकता एवं सामाजिक न्याय की दिशा में नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय की सार्थक पहल



**प्रयागराज।** नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज के विधि संकाय द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया। विधि संकाय के अधिष्ठाता डॉ. स्वप्निल त्रिपाठी एवं विभागाध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार के मार्गदर्शन तथा विधिक सहायता केंद्र के तत्वावधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा आयोजित मेगा/वृहद विधिक सेवा, जागरूकता एवं सामाजिक सहायता शिविर में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई। यह कार्यक्रम राम दुलारी बच्चू लाल जायसवाल पीजी कॉलेज, नवाबगंज, सोरांव, प्रयागराज में संपन्न हुआ। शिविर का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में किया गया, जिसका उद्देश्य समाज के निर्बल, निर्धन, दिव्यांगजन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना एवं उन्हें विधिक संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। विधिक सहायता केंद्र के पैरा लीगल वॉलेंटियर छात्र-छात्राओं ने सामाजिक न्याय एवं विधिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हुए जरूरतमंदों को विधिक परामर्श प्रदान किया।

# सरकारी पुस्तकों का गबन कर विक्रय करने वाले चार अभियुक्त गिरफ्तार, 13,082 सरकारी पुस्तकें बरामद

बहराइच।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दुर्गा प्रसाद तिवारी एवं क्षेत्राधिकारी महसी पवन कुमार के पर्यवेक्षण में थाना रामगांव पुलिस टीम को मिली सफलता, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 052/2026 धारा 3 सार्वजनिक सम्पति निवारण अधिनियम से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कुल 13082 सरकारी पुस्तकें बरामद की गईं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अशुतोष सिंह पुत्र ठेकेदार सिंह डी0सी0 शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालय की सरकारी किताबों को समद ट्रेडर्स व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिक्री हेतु ले जाये जाने की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 052/2026 धारा 3 सार्वजनिक सम्पति निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। जिसके अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा सख्त निर्देश देते हुए टीम का गठन किया गया था । जिसके क्रम में घटना के अनावरण व संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे कि थानाध्यक्ष रामगांव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर विवेचना के दौरान घटना का अनावरण करते हुए कुल 13,082 अदद सरकारी पुस्तकों की बरामदगी की गई तथा प्रकाश में आये अभियुक्तगण आलोक मिश्रा, .दिलशाद अली,शुभांकर गुप्ता एवं अर्जुन पुत्र शहजादे को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त आलोक मिश्रा, जो बी.एस.ए. कार्यालय में अनुचर के पद पर कार्यरत है और सरकारी पुस्तकों के रख-रखाव का कार्य करता है।

## जाम में रोज फंसती है दिल्ली, हर साल 60 हजार करोड़ रुपये स्वाहा, दबाव से सड़कें बन रही हैं बॉटलनेक

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कें रोजाना बढ़ती वाहनों की संख्या के चलते बेहद दबाव में हैं। आए दिन जाम से जूझती जनता शहर के लचर ट्रैफिक के लिए पुलिस और सिस्टम को दोष देती है। कई सड़कों पर बॉटलनेक जैसी स्थिति इस मुसीबत को और बढ़ा रही है। इसके चलते दिल्ली वालों के साल में 60 हजार करोड़ रुपये ईंधन समेत अन्य कारणों से स्वाहा हो रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सालाना 7,200 से 19,600 रुपये तक और उच्च-कुशल श्रमिक 25,900 रुपये तक का नुकसान झेल सकते हैं। ये खुलासा दिल्ली शहरी कला आयोग(डीयूएसी) की कुछ समय पहले आई रिपोर्ट से हुआ है। काम के दिन में सुबह वाहनों की औसत गति 41 और शाम को 56 फीसदी तक कम हो जाती है। डीयूएसी की रिपोर्ट के अनुसार, नांगलोई डिपो, एस-ब्लॉक मंगोलपुरी, आईटीओ जैसे कई चौराहे पर सड़कें संकरी और अव्यवस्थित हैं। यहां बसें, रिक्शा, पैदल यात्री और निजी वाहन एक साथ चलते हैं, जिससे जाम हमेशा बना रहता है। डीयूएसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि हर साल लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान जो होता है उसमें समय, ईंधन, प्रदूषण और दुर्घटनाएं शामिल हैं।

**निजी वाहन का बढ़ता दबाव**

सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार, देश में साल 2000 से मोटर वाहन उद्योग में भारी वृद्धि हुई है और हर 5-6 साल में नए वाहनों की संख्या दोगुनी हो जाती है। हालांकि, महामारी के कारण कुछ समय के लिए यह वृद्धि रुक गई, लेकिन अब फिर मोटर वाहन उद्योग में तेजी से सुधार हुआ और 2023-24 में औसतन प्रतिदिन 58,000 नए वाहन पंजीकृत हुए, जिनमें से 52,000 निजी वाहन थे। दिल्ली में इसी अवधि में औसतन 6.4 लाख वाहन पंजीकृत हुए और औसतन प्रतिदिन नए वाहन पंजीकृत हुए, जिनमें से लगभग 1,750 नए वाहन थे।

**1994 में 27 फीसदी जबकि 2018 में निजी वाहनों की हिस्सेदारी 48.2 प्रतिशत पहुंची**

रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है और 2015-16 से कुल नए पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 6.5 फीसदी रही। हालांकि, विदेशी वाहनों के प्रभुत्व से जुड़ी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। दिल्ली में निजी वाहनों की हिस्सेदारी साल 1994 में 27 से बढ़कर 2018 में 48.2 फीसदी हो गई और औसत यात्रा की लंबाई साल 2007 में 6 किलोमीटर से बढ़कर 2018 में 10.9 किलोमीटर हो गई, जो यात्रा की लंबाई में वृद्धि और सड़कों पर बढ़ती निर्भरता दोनों को दर्शाती है।

**बॉटलनेक क्यों बन रहे समस्या**

डीयूएसी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में सड़क नेटवर्क बेहद घना है। हर 100 वर्ग किलोमीटर में 1749 किलोमीटर सड़कें हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद वाहनों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ गई है कि सड़कें दबाव झेल नहीं पा रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के कई रास्ते बॉटलनेक की वजह से जाम का केंद्र बन चुके हैं। पूसा राउंड अबाउट पर मेट्रो और कोचिंग सेंटरों के कारण ट्रैफिक दबाव बढ़ा है।

## एआई समिट में कांग्रेस ने नंगी राजनीति की, सारी मर्यादाएं तोड़ीं- प्रधानमंत्री मोदी

**पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात; 12 हजार 930 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया शुभारंभ, बोले- अब परियोजनाएं लटकती, भटकती नहीं**

***मोदी बोले- देश जानता है कांग्रेसी पहले से नंगे**
***पीएम बनना चाहते हो तो लोगों के दिल जीतो;**
***मेरठ में रैपिड-मेट्रो रेल का उद्घाटन किया**

मेरठ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले नमो भारत RRTS का उद्घाटन किया, पूरा दिल्ली-मेरठ नमो भारत पूरा कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो (मेरठ साउथ-मोदीपुरम) देश को समर्पित किया। पीएम ने करीब 12,930 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स समर्पित किए। इससे पहले, पीएम मोदी ने नमो भारत और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी नगर से मेरठ दक्षिण स्टेशन तक सफर भी किया। इसमें 17 लोग रहे जिनमें 5 स्कूली बच्चे, चार एमबीबीएस स्टूडेंट, पांच सफाईकर्मी और तीन दिल्ली के युवा उद्यमी थे। मेरठ दक्षिण स्टेशन से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जनसभा स्थल पर मोहिउद्दीनपुर पहुंचे। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बाबा औघड़नाथ की इस पावन धरती पर आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत के लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी यह उसकी एक शानदार झांकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि एआई समिट में कांग्रेस ने नंगी राजनीति की, सारी मर्यादाएं तोड़ दीं. AI Global Summit ये भाजपा का समारोह नहीं था, ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था. लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दीं. आज पूरे देश में कांग्रेस की इस रीति-नीति पर थू-थू हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए... इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय बेशर्मी के साथ गाजते हैं. और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है. पीएम ने कहा कि एक तरफ देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल हैं जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। अभी आपने देखा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा AI Global Summit हुआ. दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए. दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ. लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी नंगी और गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया. समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए. मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं कि देश तो जानता है कि आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी. महिला सांसदों को भेज करके सीट पर कब्जा करके आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो. क्या आपलोग इतने खोखले हो गए हो कि माताओं-बहनों को इसके लिए आगे कर रहे हो. कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है.एक बात मुझे संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है. मैं इसके लिए उनका सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं.

## तमिलनाडु- बंगाल से एक बांग्लादेशी नगरिक समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार

**हमले की साजिश थी, आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से कनेक्शन; 12+ मोबाइल, 16 सिमकार्ड बरामद**

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने रविवार को 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 तमिलनाडु और 2 पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किए गए। पुलिस के मुताबिक यह सभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के इशारे पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। संदिग्धों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। इनके पास से 12 से ज्यादा मोबाइल फोन और 16 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद हुए हैं। तमिलनाडु के तिरुप्पुर से जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबत, उमर, मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट की थीं। 3 आरोपियों को उक्कुली, 3 को पल्लदम और एक आरोपी तिरुमुरुगनपोंडी से पकड़ा गया। ये सभी फर्जी आधार कार्ड के जरिए पहचान छिपाकर तिरुप्पुर में गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तमिलनाडु से गिरफ्तार 6 संदिग्धों पर आतंकियों की मदद के लिए शहरों की रेकी का आरोपी है। इसके अलावा दिल्ली में 'फ्री कश्मीर' के पोस्टर लगाने में भी शामिल होने का शक है। सभी को ट्रेन से दिल्ली लाया जा रहा है। एक दिन पहले ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने देश के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर टेरर अटैक को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दिल्ली में लाल किला, चांदनी चौक में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर स्थिति पर नजर रख रही हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। वाहनों की जांच और अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और क्विक रिएक्शन टीमें भी तैनात की गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तुरंत पुलिस या आपात सेवाओं को सूचना देने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह कदम केवल सावधानी के तौर पर उठाए गए हैं।

## अजित पवार के विमान हादसे की पहली रिपोर्ट 28 फरवरी या उससे पहले जारी की जाएगी- मुरलीधर मोहोल

नई दिल्ली । केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री और पुणे के सांसद मुरलीधर मोहोल ने रविवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता अजित पवार की जान लेने वाले विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट 28 फरवरी को या उससे पहले जारी की जाएगी। पवार और चार अन्य लोगों की 28 जनवरी को बारामती हवाई अड्डे के निकट एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यहां एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए मोहोल ने कहा, प्रारंभिक रिपोर्ट घटना के दिन से एक महीने के भीतर, 28 फरवरी को या उससे पहले जारी कर दी जाएगी। इस घटना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक और शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने कई संवाददाता सम्मेलन कर विमान कंपनी से जुड़ी कुछ अनियमितताओं और अन्य तकनीकी गड़बड़ियों का दावा किया था। उन्होंने साजिश की भी आशंका जताई थी। शनिवार को कर्जत-जामखेड के विधायक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि दुर्घटना की जांच पूरी होने तक नागर विमानन मंत्री के. राम मोहन नायडू को पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। रोहित पवार ने पत्र में कहा, वीएसआर कंपनी और राममोहन नायडू की पार्टी (तेदेपा) से इसके संबंधों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इन संबंधों की जांच एक स्वतंत्र और सक्षम प्राधिकार द्वारा की जानी चाहिए तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से। पत्र की एक प्रति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी गयी है। मोहोल ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पहले ही एक प्रेस बयान जारी कर दिया है जिसमें सर्वोच्च विमानन निकाय ने चल रही जांच से संबंधित सभी बातों पर स्पष्टीकरण दिया है।

## चुनाव आयोग 27 साल बाद करेगा गोलमेज सम्मेलन, मंगलवार को सभी राज्यों के निर्वाचन आयुक्त होंगे शामिल

नई दिल्ली ।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों (एसईसी) के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह गोलमेज सम्मेलन 27 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। इसमें निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद रहेंगे।

इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भाग लेंगे। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) भी सम्मेलन में शामिल होंगे। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, इस गोलमेज सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में अपने-अपने कानूनी ढांचों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और राज्य निर्वाचन आयुक्तों (एसईसी) के कामकाज में तालमेल को



बढ़ावा देना है। बयान में आगे कहा गया है कि विचार-विमर्श रचनात्मक विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा और निर्वाचन प्रबंधन में सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ करेगा। दिन भर चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान, निर्वाचन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के अलावा, प्रौद्योगिकी, ईवीएम और मतदाता सूचियों को साझा करने पर चर्चा होगी। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी हाल ही में शुरू किए गए ईसीआईएनईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म और निर्वाचन सेवाओं को सुव्यवस्थित करने में इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रमुख तकनीकी और परिचालन पहलों पर प्रस्तुतियां देंगे। इन प्रस्तुतियों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की मजबूती, पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा, जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1950 के संदर्भ में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार मतदाताओं की पात्रता पर एक तुलनात्मक प्रस्तुति भी दी जाएगी ताकि विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार करने को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे पर जानकारीपूर्ण विचार-विमर्श को आसान बनाया जा सके। राज्य निर्वाचन आयोगों का गठन संबंधित राज्यों के कानून द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधानों के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 243के और 243जीए के तहत पंचायतों और नगर निकायों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयुक्तों को सौंपा गया है।

## जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश के 2 आतंकी ढेर

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू क्षेत्र में आज सुरक्षाबलों और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। जिसमें संगठन का शीर्ष कमांडर समेत दो आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों के अनुसार यह एनकाउंटर तब शुरू हुआ जब सेना ने छात्रू के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। उन्हें दो संदिग्ध आतंकवादियों के इलाके में होने की सूचना मिली थी। सूत्रों के अनुसार कमांडर ने पहले भी कई बार सुरक्षा बलों को चकमा दिया था। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों की ओर से भारी गोलीबारी की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आतंकियों को ठिकाने लगाया। इस संयुक्त ऑपरेशन में जम्मू और कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ, और 2 पैराफोर्स शामिल थे। सेना के व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि सुरक्षा बलों ने रणनीतिक सटीकता और पूर्ण समन्वय के साथ मुठभेड़ स्थल पर नियंत्रण किया।

इस कार्रवाई में दो आतंकवादी सफलतापूर्वक निष्क्रिय किए गए और उनके पास से 2 एके-47 राइफलें और 5 एके मैगजीन बरामद हुई।सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और अभी भी यह सुनिश्चित करने के लिए तलाशी अभियान जारी है कि क्षेत्र में कोई और आतंकवादी मौजूद न हों।

## प्रयागराज- अविमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण मामले में एफआईआर

लखनऊ । सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए 20 साल पुरानी घटना को ढूंढ कर लाई है। यह पहली बार है जब शंकराचार्य को माघ मेले में गंगा स्नान करने से रोका गया। अखिलेश यादव रविवार को सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। जहां उन्होंने शंकराचार्य पर लगे यौन शोषण के मामले में हाईकोर्ट की ओर से एफआईआर दर्ज कराने के आदेश को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ...शंकराचार्य कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे, उस समय सर्दी चरम पर थी। हमारे सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को स्नान से रोका नहीं गया होगा लेकिन यह पहली बार हुआ है कि उन्हें स्नान से भी रोका गया... अब यह सरकार शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए 20 साल पुरानी घटना ढूंढ कर लाई...अगर यह (शिकायतकर्ता) उनका (रामभद्राचार्य) शिष्य है तो मुझसे गलती हुई है कि मैंने कभी रामभद्राचार्य पर जो मुकदमा था वह वापस लिया था, मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। विचारों को लेकर झगड़े हो जाते हैं लेकिन आप इस स्तर तक चले जाएंगे कि आप ऐसे आरोप लगवाएंगे... इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सरकार अब बचने वाली नहीं है.

## कर्नाटक में बच्चों के लिए प्रतिबंधित होगा मोबाइल फोन? सीएम ने सोशल मीडिया की लत पर जताई चिंता

बंगलूरू। कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि बच्चों में सोशल मीडिया की लत बढ़ रही है और इसका उनके दिमाग पर असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह प्रस्ताव चर्चा के दौर में है और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सलाह मांगी गई है कि क्या उनके परिसरों में नाबालिगों की मोबाइल फोन तक पहुंच को सीमित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी यहां कुलपति हैं, इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। बच्चे ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। साथ ही, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों की तरह छात्रों में मोबाइल फोन पर रोक लगाने का विचार है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। हम इसे देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि छात्रों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत उनकी शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर बुरा असर डाल रही है। इससे बच्चों के ड्रग्स के संपर्क में आने का खतरा भी बढ़ रहा है। इसके अलावा, कर्नाटक के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री प्रियांक खरगे ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राज्य खासतौर से बच्चों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग के उपायों पर हितधारकों से राय ले रहा है। कर्नाटक के अलावा, गोवा सरकार भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच से रोकने पर विचार कर रही है।

## जीतने वाली सीट पर पहला हक हमारा, संजय राउत ने आदित्य ठाकरे का नाम आगे बढ़ाया

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने रविवार को पार्टी नेता आदित्य ठाकरे के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आने वाले राज्यसभा चुनाव में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की तरफ से जीतने वाली सीट पर उनकी पार्टी का पहला हक है। इसका कारण यह है कि विपक्षी गठबंधन में उनके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं। अप्रैल महीने में कई नेताओं का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी, एनसीपी (एसपी) की फौजिया खान, आरपीआई (अठावले) के रामदास अठावले, बीजेपी के भागवत कराड, कांग्रेस की रजनी पाटिल और एनसीपी के धैर्यशील पाटिल शामिल हैं। विपक्ष के गठबंधन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के पास विधायकों की संख्या कम है। इस वजह से वे संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में अपना केवल एक ही उम्मीदवार भेज सकते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में आदित्य ठाकरे ने कहा था कि विधानसभा में उनकी पार्टी की संख्या को देखते हुए राज्यसभा सीट पर उनका हक बनता है। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने बताया कि शिवसेना (यूबीटी) के पास 20 विधायक हैं, जो विपक्ष में सबसे ज्यादा हैं। कांग्रेस के पास 16 और एनसीपी (एसपी) के पास 10 विधायक हैं।

## 12 मैचों के बाद हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका ने 76 रनों से हराया

**सेमीफाइनल की राह हुई मुश्किल**



अहमदाबाद । गत चैंपियन भारतीय टीम को टी20 विश्व कप 2026 में पहली हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने सुपर आठ चरण में भारत का विजयी अभियान रोका और उसके लिए सेमीफाइनल की राह कठिन कर दी। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 187 रन बनाए। जवाब में भारत की बल्लेबाजी काफी खराब रही और टीम 18.5 ओवर में 111 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 76 रनों से अपने नाम किया।

**एक खिलाड़ी पर निर्भरता पड़ी भारी**

भारतीय टीम के लिए एक खिलाड़ी पर निर्भरता रहना भारी पड़ा है। भारत ने ग्रुप चरण में लगभग हर मैच में एक बल्लेबाज के दम पर ही जीत दर्ज की है। यही उसी कमजोर कड़ी साबित हो रही थी और सुपर आठ के पहले मैच में टीम इंडिया की बल्लेबाजी की कलई खुल गई। भारत की बल्लेबाजी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इतनी खराब रही कि शिवम दुबे को छोड़कर अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका।

**टी20 विश्व कप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार**

भारत ने 2023 वनडे विश्व कप फाइनल के बाद आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में पहला मैच गंवाया है। किसी भी प्रारूप में भारत की आईसीसी टूर्नामेंट में 18 मैचों बाद यह पहली हार है। वहीं, 2024 टी20 विश्व कप से लेकर अब तक इस टूर्नामेंट में भारत ने लगातार 12 मैच जीते थे, लेकिन अब यह सिलसिला टूट गया है। इतना ही नहीं, टी20 विश्व कप में रनों के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी हार है। वहीं, टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम की रनों के लिहाज से यह दूसरी बड़ी हार है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भारत को 2019 में 80 रनों से हराया था।

**क्या रहे भारत की हार के कारण?**

इस मैच में भारत की हार का सबसे बड़ा कारण उसकी खराब बल्लेबाजी रही।सलामी जोड़ी का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को बड़ी शुरुआत नहीं दिला सके जिससे दबाव बढ़ा। भारत ने पावरप्ले में ही तीन विकेट गंवा दिए थे जिसके बाद टीम के लिए वापसी करना मुश्किल होता चला गया। भारत के लिए इस टूर्नामेंट में मध्य क्रम अपनी भूमिका अच्छी तरह नहीं निभा सका है और इस मैच में भी यही देखने मिला। भारत के लिए एक खिलाड़ी पर निर्भरता भी भारी पड़ी है।

**चार बल्लेबाज नहीं खोल सके खाता**

भारत की बल्लेबाजी इस मैच में इतनी खराब रही कि उसके चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। ईशान किशन, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह का खाता नहीं खुला। वहीं, तिलक वर्मा (1) और अर्शदीप सिंह (1) दहाई अंक के आंकड़े पर नहीं पहुंचे।

भारत के लिए सबसे ज्यादा रन शिवम दुबे ने बनाए जो 37 गेंदों पर एक चौका और तीन छक्कों की मदद से 42 रन बनाकर आउट हुए। इनके अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव 18, हार्दिक पांड्या 18 और वॉशिंगटन सुंदर 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को यानसेन ने चार विकेट लिए, जबकि केशव महाराज को तीन, कॉर्बिन बॉश को दो और एडेन मार्करम को एक विकेट मिला।

**ब्रेविस-मिलर की साझेदारी ने पलटा खेल**

इससे पहले मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टीम ने 20 रन तक ही तीन विकेट गंवा दिए। बुमराह ने दूसरे ओवर में सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (06) को बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई, जबकि अर्शदीप सिंह ने अगले ओवर में मार्करम (04) को मिडऑफ पर हार्दिक के हाथों कैच कराया। रेयान रिकेल्टन (07) ने अर्शदीप पर छक्का जड़ा, लेकिन अगले ओवर में बुमराह की गेंद को मिड ऑफ पर शिवम दुबे के हाथों में खेल गए। मिलर और ब्रेविस ने इसके बाद पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही अच्छी लय में नजर आए और चौथे विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी कर डाली। दक्षिण अफ्रीका के रनों का शतक 12वें ओवर में पूरा हुआ। ब्रेविस ने अगले ओवर में दुबे पर अपना तीसरा छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद को हवा में लहराकर डीप मिडविकेट पर अभिषेक के हाथों लपके गए। ब्रेविस ने 29 गेंदों पर तीन चौकों और तीन छक्कों की मदद से 45 रन बनाए।

मिलर ने दुबे के इसी ओवर में छक्के के साथ 26 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। स्टब्स ने भी वरुण पर छक्का मारा लेकिन मिलर ने लॉन्ग ऑफ पर तिलक वर्मा को कैच थमा दिया।

मिलर 35 गेंदों पर सात चौकों और तीन छक्कों के सहारे 63 रन बनाकर आउट हुए। स्टब्स ने हालांकि, अंतिम ओवर में हार्दिक पर एक चौके और दो छक्के के साथ टीम का स्कोर 190 रन के करीब पहुंचाया। भारत के लिए बुमराह ने तीन विकेट लिए, जबकि अर्शदीप को दो विकेट और वरुण चक्रवर्ती तथा शिवम दुबे को एक-एक सफलता मिली।